साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 07-13 अगस्त 2023 वर्ष-9, अंक-17 | भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित | पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा से 13 हजार रुपए तक का होगा फायदा

मध्यप्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के 20 हजार पंचायत सचिवों को अब सातवां वेतनमान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को भोपाल स्थित लाल परेड मैदान पर आयोजित पंचायत सचिवों के सम्मेलन में यह घोषणा की। इससे सचिवों को छह से 13 हजार रुपए प्रतिमाह का लाभ होगा। इसके अलावा उन्हें महीने की एक तारीख को वेतन और पीसीओ (सेक्टर प्रभारी) के पदों पर नियुक्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक घोषणाओं की झड़ी लगा दी। शिवराज ने कहा है कि ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत और सरकार के बीच सेतु की तरह कार्य करते हैं। ये सरकार को गांव की सरकार से जोड़ते हैं। उनके कार्य में निरंतरता होती है। अनेक महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं को ग्राम पंचायत सचिव ही क्रियान्वित करते हैं। आज मध्य प्रदेश आवास योजना, नल जल योजना और अन्य योजनाओं में अग्रणी है। कोविड काल में भी ग्राम पंचायत सचिवों ने लगातार कार्य किया। हाल ही में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को बहुत कम समय में धरातल पर उतारने में ग्राम पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी मेहनत और ईमानदारी सराहनीय है।

नियमित की तरह मिलेंगी सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव को विकसित, सुविधा संपन्न और आत्म-निर्भर बनाने में ग्राम पंचायत सचिव अहम भूमिका निभाते हैं। यह विकसित भारत के लिए भी जरूरी है। पंचायत सचिवों के हित में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत सचिवों को नियमित कर्मचारियों की तरह विभिन्न सुविधाएं दी जाएगी।

सीएम की घोषणाएं

- ग्राम सचिवों को 1 तारीख को ही वेतन मिल जाए, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
- मध्यप्रदेश के पंचायत सचिवों को समयमान वेतनमान भी दिया जाएगा।
- असामयिक मृत्यु पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति, नियम सरल बनाए जाएंगे।
- पीसीओ के पदों पर नियुक्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण पंचायत सचिवों को मिलेगा।
- मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायत सचिवों को पांच लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा।
- शासकीय सेवा की तरह छुट्टी व अन्य सुविधाएं ग्राम पंचायत सचिवों को मिलेगी।
- नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधा देने जरूरी प्रक्रिया प्रारंभ कर पूर्ण की जाएगी।
- सचिवों को न्यू पेंशन का लाभ भी नियमित की तरह दिया जाएगा।

मध्यप्रदेश में सड़कों पर घूम रहीं गायों के लिए जिम्मेदारों के पास कोई नहीं योजना

गौ-कैबिनेट गठित कर भूली सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

नवंबर-2020 में देश की पहली गौ-कैबिनेट गठित करके मध्यप्रदेश सरकार ने सब को चौंका दिया। तब दावा था कि प्रदेश में गायों की सुरक्षा और कल्याण के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम हो सकेगा। लेकिन दुर्भाग्य से गौ-कैबिनेट के गठन के बाद से जिम्मेदार इसे पूरी तरह से भूल गए। 18 नवंबर 2020 को इसके गठन के बाद से अब तक सिर्फ एक बैठक हुई है। ढाई साल से ज्यादा समय बीत चुका है। गावों के संवर्धन की दिशा में कोई नया काम नहीं किया गया।

सड़कों पर घूमती लावारिस गायों को तो छोड़िए गौशालाओं तक में उन्हें पर्याप्त चारा नहीं मिल पा रहा है। खास बात यह है कि गौ- कैबिनेट गठन के पहले से गायों के लिए काम कर रहे 18 साल पुराने गौ-संवर्धन गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड होने के बावजूद प्रदेशभर में एक लाख से अधिक गाय सड़कों पर ही घूमती देखी जा रही हैं।

कैबिनेट में पांच मंत्री | गौ-कैबिनेट में मप्र सरकार के पांच मंत्रियों सहित पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव को भारसाधक सचिव बनाया गया था। खुद सीएम शिवराज सिंह इसके अध्यक्ष हैं, जबकि गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, वन मंत्री विजय शाह, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, पशु पालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग डॉ. महेन्द्र सिंह सिसोदिया इसके सदस्य हैं।

लावारिस गायों की योजना नहीं

राज्य सरकार के बजट की बात करें तो साल 2022-23 में मध्यप्रदेश की पंजीकृत 1758 गौ-शालाओं में गौ-वंश के पोषण के लिए 202 करोड़ 33 लाख की राशि प्रदान की गई है। बीते वर्षों की तुलना में यह राशि भले ही दो गुना से अधिक दी गई, लेकिन इसके बाद भी मप्र में एक लाख गाय शहरों की सड़कों पर घूम रही हैं। इतन सब होने के बाद भी जिम्मेदार तमाशा देख रहे हैं।

पोर्टल पर गायों का डेटा नहीं

मध्यप्रदेश में गौ-शालाओं और उनमें गायों की संख्या को सरकारी रिकॉर्ड में समझें तो 1758 से अधिक गौ-शालाओं में 2.78 लाख से अधिक गौवंश मौजूद है, लेकिन सरकारी पोर्टल पर इसका पूरा आकड़ा गलत दिखाया जा रहा है। गौ-शालाओं की संख्या जहां 1392 बताई जा रही है, तो वहीं उनमें कुल गौ-वंश की संख्या शून्य है। विभागीय अफसर पोर्टल के आकड़े तक अपडेट नहीं रख पा रहे हैं। सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने गंभीर हैं।

स्वर्ण जयंती महोत्सवः सीएम शिवराज ने की घोषणा

मंडियों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब मंडी बोर्ड में होंगे शामिल

भोपाल। जागत गांव हमार

मप्र मंडी बोर्ड की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर भोपाल के प्रशासन अकादमी में स्वर्ण जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सब किसान हैं। हम सब सिर्फ कहने के लिए किसान नहीं है। मैंने भी खेतों में बक्खर चलाया है। हम सब मूल रूप से किसान हैं। हम आज भी खेती करते हैं। कृषि उपज मंडी की व्यवस्था के कारण हम किसानों को उचित मूल्य दिलाने में सफल हुए हैं। जो सब्जियां नीलाम होती हैं उसमें हमने तय किया कि दो प्रतिशत से ज्यादा कमीशन नहीं लिया जाएगा, लेकिन कई जगह वो कमीशन ज्यादा लगता है ऐसी कुछ मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। सीएम ने कहा हमारी कृषि विपणन बोर्ड के जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनका आमेलन भी कर लिया जाए इसका समय आ गया है। जो रह गए हैं उनको भी जोड़ने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सीएम की घोषणा के बाद प्रदेश की मंडियों में काम कर रहे करीब 22 सौ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जल्द ही मंडी बोर्ड में आमेलन किया जाएगा।

संभाग के तीनों जिलों शहडोल, उमरिया और अनूपपुर के 1000 कुओं में पानी डालने की तैयारी

प्रधानमंत्री को शहडोल के पकरिया गांव में दिखाने के लिए अफसरों ने जो तकनीक अपनाई, उसे किसानों ने सीख कर लाई सामाजिक जल क्रांति

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल के जिस पकरिया गांव में कोल, गोंड, बैगा और पनिका आदिवासियों से मिले थे, वहां सामाजिक जल क्रांति की बड़ी पहल हो रही है। पकरिया और आसपास गावों के 100 कुओं को भूजल रिचार्जिंग स्टेशन में बदल दिया गया है। मानसून में बारिश का पानी सीधे कुओं में डाला जा रहा है। जैसे ही दो-तीन दिन बारिश रुकती है, 12 से 15 फीट तक भरे हुए कुएं में 3-4 फीट पानी बचता है। यानी इतना पानी भूजल रिचार्ज हो जाता है। पकरिया का वह कुआं भी जमीन में पानी पहुंचा रहा है, जिसकी टूटी-फूटी शक्ल को मोदी के आने से पहले दुरुस्त किया गया था। दरअसल, इसी कुएं में रिचार्ज की जो तकनीक अफसरों ने दिखाई थी, वह किसान और आदिवासियों ने सीख ली।

कमिश्नर कर रहे मॉनिटरिंग

शहडोल संभाग के कमिश्नर राजीव शर्मा खुद प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वे कहते हैं कि 100 कुएं रिचार्ज करने लगे हैं, 800 की तैयारी है। कोशिश है कि संभाग के तीनों जिलों शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में कुल 1000 कुओं में ऐसे पानी डाला जाए। विकास खंड पाली के प्रभारी वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी इन कुओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत खमरौध के जमुना, पिता भूरा गोंड ने भी अपने खेत के कुएं को ऐसे जोड़ा है।

कुएं में सिर्फ जाता है पानी | खेतों में जहां भी पानी इकट्ठा हो रहा है या बहाव क्षेत्र है तो उस जगह से ट्रेंच (छोटी नाली) खोदते हैं। कुएं से 15 से 20 फीट दूर से खुदाई कर उसे कुएं के निचले भाग से जोड़ दिया जाता है। कुएं के शीर्ष से करीब 10 फीट नीचे से पानी डाल दिया जाता है। इससे मिट्टी या गाद कुएं में नहीं जाती।

ग्रामीणों को प्रशासन का सहयोग | कमिश्नर के मुताबिक, शासन का कोई खर्च नहीं लगता। हां, हम तकनीकी सहयोग देते हैं। कृषि विभाग से जुड़े संभाग के प्रभारी वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी किसानों की मदद कर रहे हैं। किसान लोकनाथ सिंह, पिता ददन सिंह ग्राम उचेहरा कहते हैं, कुआं रिचार्ज करने लगा है। अब सितंबर के बाद पता चलेगा कि कुएं में कितना पानी रहता है। भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी एलएस राजपूत देखरेख कर रहे हैं।

अश्वगंधा एक ऐसी फसल है जिसे इम्यूनिटी बूस्टर के तौर मिली पहचान

किसानों को कम समय में ज्यादा लाभ देती है अश्वगंधा की खेती

भोपाल। जागत गांव हमार

पारंपरिक फसलों की खेती छोड़कर किसान अब दूसरी तरह की फसलों की खेती कर रहे हैं, जो उन्हें कम समय में ज्यादा मुनाफा दे। अश्वगंधा की पत्तियों से लेकर जड़ तक सब बाजार में ऊंची कीमत पर बिकता है। अश्वगंधा एक ऐसी फसल है जिसे आप इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर जानते हैं।

कैसे होती है अश्वगंधा की खेती- अश्वगंधा की खेती रबी और खरीफ दोनों सीजन में की जाती है, हालांकि, खरीफ सीजन में मानसून के बारिश के बाद इसकी रोपाई करने से अच्छा अंकुरण होता है। वहीं कृषि विशेषज्ञों की मानें तो मानसून की बारिश के दौरान इसकी पौध तैयार करनी चाहिए और अगस्त या सितंबर के बीच खेत की तैयारी करके अश्वगंधा की पछेती खेती करना फायदेमंद रहता है। गौरतलब है कि इसके खेतों में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था करें, क्योंकि ज्यादा पानी अश्वगंधा की क्वालिटी को खराब कर सकते हैं। जैविक विधि से खेती करके मिट्टी में पोषण और अच्छी नमी बनाए रखने से ही अच्छा उत्पादन मिल जाता है। प्रति हेक्टेयर फसल में अश्वगंधा की खेती करने पर आपको 4-5 किलोग्राम बीजों की जरूरत पड़ती है। वहीं रोपाई, सिंचाई और देखभाल के बाद 5 से 6 महीने में अश्वगंधा की फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है। एक अनुमान के मुताबिक, प्रति हेक्टेयर जमीन में अश्वगंधा की खेती करने पर लगभग 10,000 का खर्च आता है, लेकिन फसल का हर हिस्सा बिकने के बाद आपको इससे 70 से 80 हजार रुपए की आमदनी हो जाती है।

कहां होती है अश्वगंधा की खेती

अश्वगंधा की खेती अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट या हल्की लाल मिट्टी में बेहतर होती है। भारत में इस वक्त इसकी खेती राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कई किसान कर रहे हैं। अश्वगंधा उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश और राजस्थान का नाम सबसे ऊपर है। यहां मनसा, नीमच, जावद, मानपुरा, मंदसौर और राजस्थान के नागौर और कोटा में इसकी खेती काफी बड़े पैमाने पर की जाती है।

डिमांड भारत समेत पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ी

औषधीय गुणों से भरपूर स्टीविया किसानों के लिए फायदे की खेती

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत में शुगर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे में स्टीविया की खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। दरअसल, ये एक ऐसा पौधा है जिसकी मदद से डायबिटीज पेशेंट भी मीठे का स्वाद ले सकते हैं। इसके माध्यम से कई शुगर फ्री चीजें बनाई जाती हैं। इसीलिए इसकी डिमांड भारत समेत पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ी है।

डायबिटीज में काफी फायदेमंद- इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड एवेल्यूएशन और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की 2017 की एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले 25 वर्षों में भारत में डायबिटीज के मामलों में 64 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं लैंसेट की हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में कुल 10.1 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं। जबकि 13.6 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो प्री-डायबिटीज की स्थिति में है। सबसे बड़ी बात कि द लैंसेट डाटबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित इस स्टडी को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च-इंडिया डायबिटीज ने किया है।

किसानों को कैसे होगा फायदा

स्टीविया के लिए कहा जाता है कि ये चीनी से तीन सौ गुना ज्यादा मीठा होता है। हालांकि, इसमें कैलोरीज की मात्रा शून्य होती है। यही वजह है कि डॉक्टर शुगर के मरीजों को स्टीविया से बने प्रोडक्ट लेने की सलाह देते हैं। इसलिए इसकी डिमांड खूब है। कंपनियां इसके लिए किसानों को मुह मांगा पैसा दे रही है। यही वजह है कि अब भारत में कई ऐसे किसान हैं जो इसकी खेती करते हैं। आपको बता दें स्टीविया एक जीनस पौधा है जो मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर अमेरिका से लेकर दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाया जाता है। हालांकि, अब इसकी खेती भारत के भी कुछ इलाकों में होने लगी है।

कैसे होती है खेती

स्टीविया एक ऐसी फसल है जिसे उगाने के लिए बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती। किसान चाहें तो इसे कम से कम जमीन पर भी उगा सकते हैं। हालांकि, इसकी खेती अगर आप व्यापार के तौर पर कर रहे हैं तो फिर आपको इसके लिए ऐसी जमीन तलाशनी चाहिए जो भुरभुरी, समतल और बलुई दोमट हो। ऐसी मिट्टी में इसकी फसल बेहतर होती है। और किसानों को इसका ज्यादा लाभ भी मिलता है।

ग्वालियर में हाईटेक नर्सरी और ऐरोपोनिक लैब बनेगी

भोपाल। जागत गांव हमार

ग्वालियर में हाईटेक नर्सरी के साथ ऐरोपोनिक लेब की स्थापना की जाएगी। अद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह ने विभागीय समीक्षा बैठक में हाईटेक नर्सरी और ऐरापोनिक लेब का कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।

राज्य मंत्री कुशवाह ने कहा कि विभागीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लाए। माली प्रशिक्षण कार्यक्रम में अब तक 600 युवाओं को प्रशिक्षण दिए जाने पर उन्होंने कहा अधिक से अधिक इच्छुक युवा माली प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। उद्यानिकी विभाग पांच प्रशिक्षण केन्द्र से माली प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहा है। मंत्री कुशवाह ने उद्यानिकी उत्पादों की पृथक मंडी की स्थापना के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे जाने के निर्देश दिए।

बैठक में विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण जेएन कंसोटिया, संचालक उद्यानिकी निधि निवेदिता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

लाख के पौधों की रोपाई के लिए 5.5 पीएच मान वाली मिट्टी की जरूरत

भारत में लाख की खेती से लाखों कमा सकते हैं किसान

भोपाल। जागत गांव हमार

पारंपरिक फसलों से हटकर भारत में किसान अब ऐसी फसलों की खेती कर रहें हैं जिनमें उन्हें तगड़ा मुनाफा हो। इसी कड़ में आज हम आपको एक ऐसे फसल के बारे में बताएंगे, जिसकी खेती से किसान लाखों कमा सकते हैं। सबसे अहम बात की इस फसल का नाम भी लाख से ही जुड़ा है। जी हां, लाख ही इस फसल का नाम है। दरअसल, लाख का उत्पादन कीटों द्वारा होता है और इसे कुदरती राल भी कहा जाता है। इसमें मादा कीट अपने शरीर से एक लिक्विड निकालती है और यही लिक्विड हवा के संपर्क में आकर सख्त हो जाता है।

कब होती है लाख की खेती- लाख की फसल दो बार होती है। इसमे एक कतकी अगहनी और दूसरी बैसाखी जेठवी कहलाती है। कार्तिक, बैशाख, अगहन और जेठ मास में कच्ची लाख को इकट्ठा किया जाता है। ये काम जून और जुलाई के महीने में होता है। जबकि अक्टूबर और नवंबर में लाख के बीजों को बैसाखी जेठानी फसल के लिए तैयार किया जाता है। वहीं इसके पौधों की रोपई की बात करें तो लाख के पौधों की रोपाई के लिए 5.5 पीएच मान वाली मिट्टी की जरूरत होती है। वहीं पौधों की रोपाई करते वक्त एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर के बीच होती है।

छत्तीसगढ़ में खूब होती है लाख की खेती

छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में लाख की खेती जीवनयापन का अहम हिस्सा है। वहीं अब इसकी खेती के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को सही ट्रेनिंग और सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध करवाने का भी फैसला किया है। आपको बता दें यहां लाख की क्रय दर 550 रुपए प्रति किलो है, जबकि रंगीनी बीहन लाख यानी पलाश के पेड़ से निकाली गई लाख की क्रय दर 275 रुपए प्रति किलोग्राम है। जबकि, बेर के पेड़ से प्राप्त लाख के लिए किसानों को देय विक्रय दर 640 रुपए प्रति किलोग्राम रखी गई है। वहीं रंगीनी बीहन लाख यानी पलाश के पेड़ों से प्राप्त लाख के लिए विक्रय दर 375 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है।

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर किसान कर सकते हैं आवेदन

किसान ड्रोन पर सरकार दे रही है 50 प्रतिशत अनुदान

ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस अपलोड करना अनिवार्य होगा

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन संचालन के लिए ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस को रखने की बाध्यता रखी गई है। संचालनालय द्वारा किसान ड्रोन क्रय के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अनुदान योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के कृषक/कस्टम हायरिंग केन्द्र संचालक/कृषक उत्पादन संगठन (एफपीओ) श्रेणीयों के अंतर्गत इच्छुक कृषक/केन्द्र संचालक/संस्था 8 अगस्त, 2023 से ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

आवश्यक नियम व शर्तें- संचालक कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन के साथ धरोहर राशि 5000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट एवं ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस अपलोड करना अनिवार्य होगा। लायसेंस स्वयं का अथवा उनके प्रतिनिधि का हो सकता है। डिमांड ड्राफ्ट संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनाना होगा। जिन आवेदनों के साथ धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न नही पाया जाएगा वे अस्वीकार किए जाएंगे। किसान ड्रोन को क्रय करने के लिए अनुदान प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित है।

न्यूनतम अर्हता एवं शुल्क

प्रशिक्षण में भाग ले रहे आवेदक/प्रतिनिधि के लिये निर्धारित शुल्क एवं न्यूनतम अर्हताएं निम्नानुसार निर्धारित है। आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष हो, कक्षा 10 वी (दसवी) उत्तीर्ण हो तथा संबंधित का वैध भारतीय पासपोर्ट उपलब्ध होना चाहिए। उपरोक्त प्रशिक्षण का शुल्क राशि 30,000 रुपए जीएसटी अनिरिक्त का शुल्क नियत किया गया है। उपरोक्त शुल्क में से 50 प्रतिशत अधिकतम 15,000 रुपए एवं जीएसटी अभ्यार्थियों को वहन करना होगा। शेष 50 प्रतिशत राशि शासन द्वारा वहन की जाएगी। उपरोक्त आवासीय प्रशिक्षण 07 दिवसीय (5 दिवसीय डीजीसीए द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण एवं 2 दिवसीय किसान ड्रोन संचालन) है। आवास एवं भोजन की व्यवस्था नि:शुल्क है, जो आवेदक/प्रतिनिधि उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते हैं, वे अपना ऑनलॉईन आवेदन कर जाकर कौशल विकास केंद्र का चयन कर अपनी जानकारी एवं अभिलेख अपलोड करें। संबंधित कौशल विकास केन्द्र के अधिकारी के द्वारा पंजीकृत आवेदक के दस्तावेजों का सत्यापन कर अभ्यार्थियों का चयन बैच की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा। प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पूर्व संबंधित आवेदक को सूचित किया जाएगा। आवेदक/प्रतिनिधि को उपस्थिति के समय अपलोड किए गए अभिलेखों को मूल अभिलेखों के साथ मिलान कराना होगा। यदि किसी प्रकार की विसंगति प्राप्त होती है, तो संबंधित आवेदक/प्रतिनिधि को प्रशिक्षण में भाग लेने से अपात्र किया जा सकेगा।

अनुदान पात्रता व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत लघु , सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के लिए यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 5,00,000 रुपए अनुदान, व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत अन्य वर्ग के कृषकों एवं कस्टम हायरिंग केन्द्रों के संचालकों के लिए यंत्र की कीमत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि 4,00,000 रुपए अनुदान तथा कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के लिए यंत्र की कीमत का 75 प्रतिशत अधिकतम राशि 7,50,000 रुपए अनुदान की पात्रता होगी। जिन आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों के पास ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस नहीं है तथा यदि वे प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र से ड्रोन पायलट लायसेंस प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने पर चयनित आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों को अनुदान पर किसान ड्रोन का क्रय करने की पात्रता होगी।

अधिकारियों ने कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपा

वरिष्ठता के आधार पर कृषि विभाग में खाली पड़े पदों को भरने की मांग

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश कृषि विभाग में पदोन्नति न होने के कारण कृषि अधिकारियों में रोष व्याप्त है जबकि प्रथम श्रेणी के कई पद रिक्त पड़े हैं। इसे देखते हुए गत दिनों कृषि अधिकारियों ने वरिष्ठता के आधार पर रिक्त पदों का प्रभार देने के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधिकारियों ने कहा कि प्रमोशन का लाभ लिए बिना ही हर माह बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं जिस कारण किसानों को योजनाओं का समय पर उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सहायक संचालकों को उप संचालक एवं परियोजना संचालक आत्मा के कुल 71 पदों का, उपसंचालक एवं परियोजना संचालक आत्मा को संयुक्त संचालकों के 17 पदों का तथा संयुक्त संचालकों को अपर संचालकों के कुल 7 पदों का प्रभार दिया जाए।

योजनाओं का संचालन सुचारू रूप से हो सके

कृषि अधिकारियों ने बताया कि कई विभागों जैसे- शिक्षा, चिकित्सा, राजस्व एवं गृह में वरिष्ठता के आधार पर प्रभार दिया गया है। इसी प्रकार कृषि विभाग में भी प्रभार दिया जाए। ज्ञातव्य है कि प्रदेश में उपसंचालक एवं परियोजना संचालक आत्मा के कुल 143 स्वीकृत पदों में से इस वर्ष के अंत तक 71 पद रिक्त होंगे। इसी प्रकार संयुक्त संचालक के कुल 22 स्वीकृत पदों में से 17 पद रिक्त होंगे तथा अपर संचालकों के प्रतिनियुक्ति सहित कुल 11 स्वीकृत पदों में से वर्ष 2023 के अंत तक 7 पद रिक्त होंगे। उक्त स्थिति के मद्देनजर अधिकारियों ने वरिष्ठता के आधार पर प्रभार देने की मांग की है जिससे शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके।

काले अंगूर की खेती किसानों को कर सकती है मालामाल

भोपाल। जागत गांव हमार

काले अंगूर में भरपूर औषधीय गुण होते हैं। इसकी खेती से किसानों को अच्छा आर्थिक लाभ हो सकता है। दरअसल, काले अंगूरों से ही काली किशमिश बनती है। इसलिए सही सवाल तो ये है कि काले अंगूर की खेती कैसे होती है। तो आपको बता दें, काले अंगूर की भारत में खेती महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में होती है। वहीं इनकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त कंकरीली, रेतीली और चिकनी मिट्टी होती है।

काले अंगूर के बाग अगर आपने एक बार लगा दिए तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपक एक या दो साल ही फल देंगे। अगर इनका ठीक से ख्याल रखा जाए तो एक बार लगाए गए बाग कम से कम दस साल तक अंगूर की फसल देते हैं। यानी इसकी खेती में लागत कम मुनाफा ज्यादा है।

औषधीय गुणों से भरपूर है काला अंगूर

काले अंगूर में अमीनो एसिड, आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, कैल्शियम और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलते हैं। ये आपके शरीर के लिए भी फायदेमंद होता है। इससे हमारे शरीर की इम्युनिटी बूस्ट होती है और यह हमारे शरीर से खून की कमी को भी पूरा करता है।

कपास फसल के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम देय होगी

सरकार ने बढ़ाई फसल बीमा की अंतिम तारीख अब 16 अगस्त तक होगा खरीफ फसलों का बीमा

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ वर्ष-2023 की फसलों का बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई थी, लेकिन कृषकों की सुविधा को देखते हुए फसलों का बीमा कराने की तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी गई है। ऋणी तथा अऋणी कृषक संबंधित बैंकों में इस अवधि में अपनी फसल का बीमा कराकर योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। अऋणी कृषक अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, कॉमन सर्विस सेन्टर या प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर जाकर स्वयं सोयाबीन, मक्का, कपास, बाजरा, अरहर जौ, मूंगफली, मूंग एवं उडद फसलों का बीमा करवा सकते हैं। वहीं ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंको के माध्यम से ही किया जाएगा।

जरूरी दस्तावेज योजना का लाभ लेने के लिए कृषकों को आवश्यक दस्तावेज के रूप में फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे मतदाता परिचय-पत्र राशन कार्ड, पेन कार्ड, भू-अधिकार पुस्तिका, खसरा-खतोनी, बोवनी प्रमाण पत्र पटवारी एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। कृषि विभाग ने समस्त किसान भाइयों से अपील की है कि 16 अगस्त तक अधिक से अधिक संख्या में प्रधानमंत्री फसल बीमा कराकर योजना का लाभ लेने हेतु अधिसूचित फसल सोयाबीन, मक्क, बाजरा, अरहर, मूंगफली, जौ, मूंग एवं उड़द के लिये कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 2 प्रतिशत तथा कपास फसल के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम देय होगी।

भूमि को उपजाऊ बनाने भूमि सुधार को प्राथमिकता देना आवश्यक

अभी तो पानी की अधिकता है, लेकिन जब फसलों की सिंचाई का वक्त आता है तो पानी की कमी देखी जाती है और किसान नहरों में पानी आने का इंतजार करते हैं या फिर भूजल का दोहन करते हैं। भारत में बड़े पैमाने पर नहरों से सिंचाई हो रही है। नहर-नालियों से होकर पानी जब खेतों में पहुंचता है तो अपने साथ कई तरह के लवण और विशेष रूप से सोडियम क्लोराइड यानी नमक भी कृषि भूमि पर ला छोड़ता है।

भूजल में भी सोडियम क्लोराइड की अधिकता भूमि की उपजाऊ शक्ति घटाता है। नहरों के पानी या भूजल से आने वाले लवण मिट्टी की ऊपरी सतह में ही रह जाते हैं। इनकी मात्रा बढ़ती जाती है, क्योंकि उसे निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है।

जिन खेतों पर दशकों से सिंचाई हो रही हो, वहां लवणता की समस्या विकराल रूप लेती जाती है और भूमि की उत्पादन क्षमता घटने के साथ वह ऊसर बन जाती है। इस तरह के उदाहरण विभिन्न राज्यों की कृषि भूमि पर प्राय: देखे जाते हैं।

चूंकि तटीय क्षेत्रों पर समुद्री तूफान, चक्रवात आदि का प्रकोप प्राय: होता रहता है इसलिए वहां समुद्री पानी, जो अत्यंत खारा होता है, भूमि की उत्पादन क्षमता एक-दो दिन में ही समाप्त कर देता है। इसके लिए एकमात्र निदान उपसतही जलनिकासी प्रणाली यानी सब-सर्फेस ड्रेनेज सिस्टम है। यह एक तरह की तकनीक है, जिसमें कई तरह की नालियां होती हैं। इन नालियों के माध्यम से भूमि से लवण को बाहर किया जाता है। चार दशक पहले इस तकनीक के नेटवर्क को सिर्फ मजदूरों की मदद से स्थापित किया जाता था। आज उन्हें पूर्णत: मशीनों की मदद से तेज गति से स्थापित किया जाने लगा है। इस लवणीय भूजल का प्रयोग झींगा संवर्धन के उपयोग में लाया जा सकता है।

कृषि विज्ञानियों तथा इंजीनियरों द्वारा विकसित उपसतही जलनिकासी तकनीक लवणता से ग्रस्त भूमि अथवा खारी मिट्टी वाली अनुपजाऊ भूमि को दो-तीन वर्ष में ही उपजाऊ बना देती है। बीते दशकों में नीदरलैंड की मदद से हरियाणा और कनाडा की मदद से राजस्थान में इस तकनीक का प्रयोग कर दोनों राज्यों में 20 से 40 हजार हेक्टेयर लवणता ग्रस्त एवं जलभराव से प्रभावित भूमि को कृषि योग्य बनाया गया।

कृषि विज्ञानियों के शोध में यह ज्ञात हुआ कि जिन लवणता ग्रस्त खेतों पर उत्पादकता 500 किग्रा प्रति हेक्टेयर होती थी, वहां पर उपसतही जलनिकासी तकनीक से कृषि उत्पादकता 2000-2500 किग्रा प्रति हेक्टेयर हो गई। विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि भारत में लवणता और जल भराव से प्रभावित क्षेत्रफल करीब 80-90 लाख हेक्टेयर है और आने वाले समय में यदि सही कदम नहीं उठाए गए तो यह क्षेत्रफल और अधिक बढ़ सकता है।

यदि कृषि योग्य भूमि सुधार हेतु इस तकनीक का उपयोग समय से न किया जा सका तो समस्या विकराल रूप ले सकती है। इससे खाद्यान्न उत्पादन घट सकता है।

भारत विश्व के 2.4 प्रतिशत भौगोलिक भूभाग एवं चार प्रतिशत जल संसाधन की मदद से अपनी अन्न संबंधी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भारत अब चीन से आगे निकलकर प्रथम स्थान पर आ गया है। बढ़ती जनसंख्या और घटती हुई उपजाऊ भूमि कृषक समुदाय की वर्तमान पीढ़ी एवं भावी पीढ़ी को भी चिंतित किए हुए है।

कृषि व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों में असुरक्षा की भावना न रहे, इसके लिए सब-सर्फेस ड्रेनेज सिस्टम अपनाना आवश्यक है। इस मामले में वर्तमान सरकार द्वारा सृजित सहकारिता मंत्रालय की भूमिका बहुत प्रासंगिक और उपयुक्त होगी। मृदा लवणता से प्रभावित राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब आदि में उपसतही जलनिकासी तकनीक के प्रयोग से लाखों हेक्टेयर अनुपजाऊ भूमि की मिट्टी के स्वास्थ्य को सतत उपजाऊ बनाए रखा जा सकता है।

वर्तमान सरकार कृषक समुदाय को आत्मनिर्भर करने के लिए प्रयत्नशील है। इसमें सफलता के लिए कृषि योग्य भूमि को उपजाऊ बनाए रखना आवश्यक है। भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए सिंचाई एवं जलनिकासी तंत्र की अवसंरचना को 2015 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने बहुत सशक्त किया है, पर भूमि से लवण निकालने का अभ्यास बिल्कुल नहीं किया जा रहा है।

स्पष्ट है कि भूमि सुधार को प्राथमिकता देना नितांत आवश्यक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की सफलता को पूर्णता तब प्राप्त होगी, जब यह भी पता किया जाए कि किन-किन क्षेत्रों में मिट्टी की लवणता की समस्या गंभीर है। जहां कृषि उत्पादकता नगण्य हो गई हो, वहां कृषि भूमि को उपजाऊ बनाए रखने में एकमात्र उपाय उपसतही जलनिकासी तकनीक ही रह जाती है। इस तकनीक का इस्तेमाल नीदरलैंड, अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोपीय देशों में किया जा रहा है।

सहकारी व्यवस्था के तहत केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रयासों से भूमि को उपजाऊ बनाने का काम आरंभ करना बहुत सुगम होगा। कृषि भूमि को उपजाऊ बनाने की इस परियोजना में औसतन 1.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की लागत आ सकती है। यह हमेशा लाभकारी सौदा ही होगा, क्योंकि भूमि अधिग्रहण में एक हेक्टेयर भूमि का मुआवजा लगभग ढाई से तीन करोड़ रुपये देना पड़ता है। भूमि सुधार के इस कार्यक्रम के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इससे उपजाऊ कृषि भूमि की उपलब्धता बढ़ जाएगी और भूमि अधिग्रहण कानून बनाने में भी आसानी हो जाएगी।

गांवों में ब्राडबैंड: ग्रामीण क्षेत्र में आएगी डिजिटल क्रांति

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना इसलिए हमारे नीति-नियंताओं की प्राथमिकता सूची में होना चाहिए, क्योंकि भारत की अधिसंख्य आबादी अभी भी गांवों में निवास करती है। गांवों के ब्राडबैंड से जुड़ने से उनमें कारोबारी गतिविधियों को बल मिलने की भी उम्मीद की जा रही है। इससे स्वाभाविक रूप से जीएसटी संग्रह में भी वृद्धि होगी और इसका लाभ पूरे देश को भी मिलेगा। यह अच्छा हुआ कि केंद्रीय कैबिनेट ने 6.4 लाख गांवों को ब्राडबैंड से जोड़ने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी। आशा की जानी चाहिए कि अब इस पूरी योजना को धरातल पर उतारने में कहीं अधिक आसानी होगी। अभी लगभग दो लाख गांवों में ब्राडबैंड इंटरनेट की सेवा पहुंच चुकी है। यदि इस योजना पर सही ढंग से समय रहते अमल किया जा सके तो भारत का ग्रामीण क्षेत्र भी निश्चित रूप से डिजिटल क्रांति में शामिल होगा। चूंकि यह दौर डिजिटल युग का है, इसलिए इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के भरे-पूरे आसार हैं।

ग्रामीण अर्थव्यस्था को सुदृढ़ करना इसलिए हमारे नीति-नियंताओं की प्राथमिकता सूची में होना चाहिए, क्योंकि भारत की अधिसंख्य आबादी अभी भी गांवों में निवास करती है। गांवों के ब्राडबैंड से जुड़ने से उनमें कारोबारी गतिविधियों को बल मिलने की भी उम्मीद की जा रही है। इससे स्वाभाविक रूप से जीएसटी संग्रह में भी वृद्धि होगी और इसका लाभ पूरे देश को भी मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही सरकार को यह भी देखना होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे और अधिक संस्थागत स्वरूप ले। यह इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में जिस अनुपात में वृद्धि हो रही है, उसके अनुरूप टैक्स का दायरा बढ़ नहीं पा रहा है। जहां तक गांवों की बात है तो उनमें आय के साधनों के साथ ही लोगों की डिजिटल पहुंच बढ़ रही है और कारोबारी गतिविधियों का क्षेत्र भी विस्तृत हो रहा है, लेकिन बात चाहे जीएसटी संग्रह की हो अथवा आयकर की, ग्रामीण अर्थव्यस्था कुल मिलाकर पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। यह ठीक है कि औसत किसान साधन संपन्न नहीं हैं और उनकी आय भी सीमित है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग हैं ही नहीं जो अच्छी-खासी कमाई न करते हों। विडंबना यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अति धनाढ्य और बड़ी आय वाले किसान भी टैक्स के दायरे से बाहर हैं।

यह सही समय है जब इस पर विचार किया जाए, कि जिनकी अच्छी-खासी आय है और जो टैक्स देने में समर्थ हैं, उन्हें आयकर के दायरे में लाया जाए। ऐसा करना गांवों की अपनी खुशहाली और बेहतरी के लिए भी आवश्यक है। सरकार ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए हैं, लेकिन उनकी सार्थकता तभी है जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा सशक्त और पारदर्शी होगा। अगर सरकार सभी गांवों को ब्राडबैंड से जोड़ने की पहल को आर्थिक विकास के एक अहम पहलू के रूप में देख रही है तो उसे कृषि की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से टैक्स की प्रणाली पर नए सिरे से निगाह डालनी चाहिए।

लाखों गांवों में पहुंचेगा तेज स्पीड वाला इंटरनेट: मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 6.4 लाख गांवों को ब्रॉडबैंक संपर्क से जोड़ने के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 1.94 लाख गांवों को जोड़ा जा चुका है और शेष गांवों को ढाई साल में जोड़ने की संभावना है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल ने शुक्रवार शाम को हुई बैठक में देश के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर आधारित कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए 1,39,579 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है।

गांव-गांव ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचाएगा बीएसएनएल: अंतिम छोर तक संपर्क बीएसएनएल की शाखा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ग्राम स्तरीय उद्यम के साथ मिलकर उपलब्ध कराएगी।

सूत्रों ने बताया, स्थानीय उद्यमियों की मदद से फाइबर को घर-घर पहुंचाने के मॉडल को एक प्रायोगिक परियोजना के सफल समापन के बाद अंतिम रूप दिया गया।

इस परियोजना के तहत घरों को जोड़ने के लिए आवश्यक उपकरण और अतिरिक्त फाइबर क्ष्क्ष्रद्वारा प्रदान किए जाते हैं, और स्थानीय उद्यमियों को नेटवर्क के रखरखाव का काम सौंपा गया है।

क्या होगी ब्रॉडबैंड योजना की कीमत: एक सूत्र ने कहा, लगभग 60,000 गांवों के लिए चलाई गई प्रायोगिक परियोजना में लगभग 3,800 उद्यमी शामिल थे, जिन्होंने 3.51 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराए। प्रति घर औसत डेटा खपत प्रति माह 175 गीगाबाइट दर्ज की गई है।

यह परियोजना बीबीएनएल और बीएलई के बीच 50 प्रतिशत राजस्व-साझाकरण के आधार पर शुरू की जा रही है, और मासिक ब्रॉडबैंड योजना की कीमत 399 रुपये से शुरू होती है।

कितनी फैलाई गई केबल: सूत्रों के अनुसार, देशभर में ऑप्टिकल फाइबर केबल की 37 लाख रूट किलोमीटर फैली हुई है, जिसमें से बीबीएनएल ने 7.7 रूट किलोमीटर बिछाई है।

चावल पर प्रतिबंध का प्रभाव

सरकार ने बासमती तथा उसना चावल को छोड़कर हर प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का यह निर्णय राजनीतिक बाध्यताओं से प्रेरित है। ऐसा शायद इसलिए किया गया है ताकि कुछ अहम राज्यों के विधानसभा चुनावों और अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले घरेलू आपूर्ति और कीमतों का बचाव किया जा सके। परंतु इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमतें 11 वर्ष के उच्चतम स्तर पर हैं तथा उनमें और इजाफा होने लगा है। कुछ मामलों में तो जो माल रास्ते में है उसकी कीमत भी 50 से 100 डॉलर प्रति टन तक बढ़ गई है। भारत पिछले कुछ समय में दुनिया का शीर्ष चावल निर्यातक रहा है और उसने वैश्विक व्यापार का करीब 40 फीसदी अनाज निर्यात किया। वर्ष 2022-23 में उसने 2.23 करोड़ टन चावल निर्यात किया। उसके अचानक इस बाजार से बाहर हो जाने से वैश्विक आपूर्ति में करीब एक करोड़ टन की कमी आएगी।

गैर खुशबूदार चावल के अन्य निर्यातकों में थाईलैंड और वियतनाम के पास इस कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त चावल का भंडार नहीं है। इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न की अंतरराष्ट्रीय कीमतें जो पहले ही मौसम के कारण उपज से जुड़ी अनिश्चितताओं, रूस द्वारा यूक्रेन को काला सागर बंदरगाहों के जरिये अनाज निर्यात की इजाजत वापस लेने के कारण बढ़ी हुई थीं उनमें और तेजी आई है। इससे खाद्यान्न संकट से जूझ रहे देशों की चिंताएं बढ़ेंगी। खासतौर पर छोटे अफ्रीकी देशों की जो भारत से आने वाले अनाज पर निर्भर करते हैं।

आश्चर्य नहीं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भारत द्वारा निर्यात प्रतिबंध को लेकर आक्रामक रुख दिखाया और कहा कि इससे वैश्विक खाद्य कीमतों की अस्थिरता की स्थिति और बिगड़ सकती है। उन्होंने भारत से कहा है कि उसे यह प्रतिबंध हटा लेना चाहिए। देश में भी सरकार के कदम को समझदारी भरा नहीं माना जा रहा है। इसकी कई वजह हैं। एक बात तो यह कही जा रही है कि ऐसा करके भारत आकर्षक वैश्विक कीमतों से फायदा उठाने से चूक रहा है। इसके अलावा यह इस लिहाज से भी नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि किसान धान की खेती का रकबा बढ़ाने को लेकर हतोत्साहित होंगे और वे उपज बढ़ाने वाले साधनों का प्रयोग भी नहीं करेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे खाद्यान्न के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता और विश्वसनीय व्यापारिक साझेदार की भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचेगा।

इसमें दो राय नहीं है कि चावल की घरेलू कीमतों में साल भर में करीब 11.5 फीसदी का इजाफा हुआ है लेकिन इस इजाफे की एक वजह न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा भी है। निश्चित रूप से स्थानीय बाजारों में चावल की कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार भारतीय खाद्य निगम के कुल अनाज भंडार में कमी आई है लेकिन चावल का भंडार अभी भी 4.1 करोड़ टन से अधिक है यानी 1.35 करोड़ टन की बफर स्टॉक सीमा से काफी अधिक। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सरकार की 3.6 से 3.8 करोड़ टन की आवश्यकता से काफी अधिक है। यह आशंका भी कमजोर हुई है कि उभरते अल नीनो प्रभाव के कारण मॉनसून तथा धान की खेती प्रभावित होगी। अब तक तो मॉनसून देश भर में सामान्य से बेहतर रहा है और धान की बोआई उन इलाकों में भी काफी अच्छी है जहां पिछले साल यह इस समय कमजोर रही थी। ऐसे में सरकार को यही सलाह होगी कि वह बाजार को ऐसे झटके देने वाले निर्णय न ले और यह सुनिश्चित करे कि घरेलू और बाहरी खाद्यान्न व्यापार नीतियों में स्थिरता बरकरार रहे।

आधुनिक खेती ने युवाओं के लिए सुनहरे भविष्य के दरवाजे खोले

कृषि की पढ़ाई में भी है अच्छा भविष्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि

आधुनिक तकनीक के प्रयोग ने नई संभावनाओं को जन्म दिया...

भोपाल। जागत गांव हमार

समय के साथ कृषि क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ी हैं। आधुनिक खेती ने युवाओं के लिए सुनहरे भविष्य के दरवाजे खोले हैं। आधुनिक तकनीक के प्रयोग ने नई संभावनाओं को जन्म दिया है। युवाओं का रुझान भी इस फील्ड की ओर बढ़ा है। एग्रीकल्चर के कई कोर्स इन दिनों टॉप ट्रेंड में हैं, जिनकी मदद से आप भी लाखों की नौकरी पा सकते हैं।

देश की बड़ी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। वैज्ञानिक तरीके से खेती किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है। वहीं मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में भी यह कारगर साबित होती है। किसान अपने खेत की मिट्टी आदि का परीक्षण कराकर ही खेती में डाले जाने वाले उर्वरकों के अनुपात को तय कर रहे हैं। जगह-जगह कृषि विज्ञान केंद्र खुल गए हैं और प्रयोगशालाओं में खेतों की मिट्टी आदि की सेहत जांची जा रही है। ऐसे में एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, हॉर्टीकल्चर, फूड और होम साइंस जैसे किसी क्षेत्र में पढ़ाई कर आप अपने करियर को संवार सकते हैं। कृषि क्षेत्र में मार्केटिंग और मैनेजमेंट क्षेत्र में भी अच्छा करियर बनाया जा सकता है।

क्या है योग्यता

आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ-मेटिक्स या बायोलॉजी से 12 वीं पास हों। कृषि वैज्ञानिक बनने के लिए एग्रीकल्चर में बीई या डिप्लोमा करना होगा। प्रोफेशनल कोर्स के लिए संबंधित विषयों में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए।

ये हैं स्पेशलाइज्ड कोर्स

एग्रीकल्चरल फिजिक्स
एग्रीबिजनेस
प्लांट पैथोलॉजी
प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स
प्लांटेशन मैनेजमेंट
यहां से करें कोर्स
इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली
इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट
नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट
इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट

कृषि क्षेत्र में नौकरियों की भरमार

कृषि क्षेत्र में नौकरी के तमाम मौके युवाओं को हर साल मिलते हैं। आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में नौकरी का मौका तो हर साल मिलता ही है। यूपीएससी एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट की नियुक्ति के लिए परीक्षा कराता है। आप चाहें तो खेती से जुड़े अन्य क्षेत्रों में जॉब की तलाश कर सकते हैं। कई कंपनियां एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को जॉब देती हैं। बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड, लोन आदि से जुड़े कार्य में ये ग्रेजुएट किसानों की मदद कर सकते हैं। बैंक के फील्ड ऑफिसर की जॉब के लिए एग्रीकल्चर का अनुभव रखने वाले शख्स को बेहतर समझा जाता है।

वन विहार में एक माह चलेगा नेचर केम्प

भोपाल। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू में छात्र-छात्राओं को वन, वन्य-प्राणियों और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से भोपाल एवं आसपास के ग्रामों के शासकीय एवं अशासकीय

विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिये अगस्त माह में प्राकृतिक हरियाली में 30 नेचर केम्प का आयोजन किया जा रहा है। श्रंखला के प्रथम दिन मंगलवार एक अगस्त से केम्प का आयोजन किया गया, नेचर केम्प में रिसोर्स पर्सन के रूप में श्री एके खरे सेनि, उप वन संरक्षक और मोहम्मद खलीक ने पक्षियों एवं वन्य-प्राणियों के बारे में छात्र-छात्राओं को रोचक जानकारी दी। वन विहार में भ्रमण के दौरान तितली पार्क में बच्चों को विभिन्न तितलियों एवं उनके जीवन चक्र से संबंधित जानकारी दी गई। इसके साथ ही बाड़े में रखे गये वन्य-प्राणियों का भी अवलोकन कराया गया। वन्य-प्राणियों को देख कर छात्र-छात्राएं उत्साहित हुए। वन विहार में 30 अगस्त तक प्रतिदिन विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं को नेचर केम्प में शामिल किया जाएगा।

मगरपाटी बैराज सिंचाई परियोजना को स्वीकृति

भोपाल। पशुपालन मंत्री प्रेमसिंह पटेल की पहल पर बडवानी जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा मगरपाटी बैराज सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। परियोजना की स्वीकृति मिलने से

हजारों किसानों को फायदा होगा। पशुपालन मंत्री पटेल ने बताया कि किसानों द्वारा मगरपाटी बैराज सिंचाई परियोजना की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इस संबंध में शासन को पत्र भेज कर अवगत कराया गया था। परियोजना को स्वीकृति प्राप्त होने से क्षेत्र के किसान 455 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई कर सकेंगे। मंत्री पटेल ने बताया कि 781 लाख की लागत से शुरू होने जा रही सिंचाई परियोजना से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी मिलेगा, साथ ही सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा। मगरपाटी बैराज सिंचाई परियोजना की जल्द ही निविदा आमंत्रित कर शीघ्र ही परियोजना का कार्य प्रारंभ कराया जाएगा।

एसडीएम ने मूंग खरीदी केंद्रों पर मारा छापा, लापरवाहों में मचा हड़कंप

अमृत प्रभा वेयरहाउस से जब्त की सौ क्विंटल अमानक मूंग

सरकार सख्त ऑन लाइन पंजीयन अब होंगे निरस्त

पिपरिया। जागत गांव हमार

गत दिवस एसडीएम ने कलेक्टर के निर्देश पर समर्थन मूल्य मूंग खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पचमढ़ी रोड अमृत प्रभा वेयर हाउस में भारी अनियमितताएं सामने आई है। निरीक्षण के दौरान कृषि विभाग और खाद्य विभाग के अधिकारी भी साथ रहे। सरकारी मूंग खरीदी में घालमेल की शिकायतों के बाद कलेक्टर नर्मदापुरम नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर एसडीएम संतोष तिवारी ने मंगलवार को पिपरिया सरकारी मूंग खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया अमृत प्रभा वेयरहाउस में जांच के दौरान मौके पर ही करीब 100 क्विंटल अमानक मूंग के ढेर जब्त किए गए हैं। साथ ही वारदानों पर सील नहीं मिली और किसानों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नही थी।

एसडीएम ने वेयर हाउस मालिक और खरीदी एजेंट को फटकार लगाते हुए कहा कि अमानक मूंग वेयर हाउस के अंदर कैसे पहुंची। उन्होंने वेयर हाउस मालिक से कहा अगर वे यहां रहे तो यह केंद्र मूंग खरीदी केंद्र नही बनेगा। एसडीएम ने कृषि एसडीओ निराली आर्य को अमानक मूंग पंजीयन को ऑनलाइन रिजेक्ट करने के निर्देश दिए।

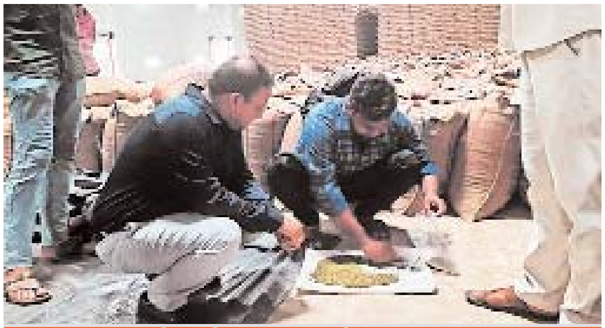

बिचौलियों की भी मिलीभगत

एसडीएम ने बताया सोमवार को बनखेड़ी चादोंन खरीदी केंद्र चेक किया यहां भी करीब 100 क्विंटल अमानक मूंग जब्त की। यह चर्चा आम हैं की घटिया किस्म की मूंग खरीदी एजेंटों के घालमेल के जरिए बेची जा रही है। इससे आम किसान परेशान होता है घपला करने वाले ऐश करते है। किसानों का कहना है सभी केंद्रों पर यह अनियमितता हो रही है। किसान तीन-तीन दिन मूंग बेचने पड़े रहते हैं। एसडीएम ने बताया कि अमृत प्रभा के अलावा मां शारदा वेयर हाउस खिड़िया का भी निरीक्षण किया। यहां 70 क्विंटल नॉन एफएक्यू मूंग मिली, इसे रिजेक्ट कराया गया है। धनाश्री खरीदी केंद्र सहित अन्य केंद्र की भी जांच हुई। इस दौरान कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मनोज शुक्ला, डबल लॉक नोडल अधिकारी भारत निमोदा मौजूद रहे।

प्रबंध संचालक मंडी ने कृषि उपज मंडी समिति बैरसिया में पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया

भोपाल। जागत गांव हमार

कृषि उपज मंडी समिति बैरसिया जिला भोपाल में स्वर्ण जयंती महोत्सव श्रंखला के उपलक्ष मे प्रबंध संचालक गौतम सिंह साहब द्वारा वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनके द्वारा कृषि उपज मंडी समिति बैरसिया में आम वृक्ष का रोपण कर पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपर संचालक डॉ. एसबी सिंह, चंद्रशेखर वशिष्ठ आंचलिक कार्यालय भोपाल की संयुक्त संचालक रितु चौहान, संगीता ढोके अधीक्षण यंत्री डीएस राठौर चीफ प्रोग्रामर संदीप चौबे तथा मंडी समिति बैरसिया के सचिव प्रताप सिंह राजपूत के साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। पौधरोपण कार्यक्रम में फलदार पौधे के साथ-साथ फूलों के पौधों का रोपण भी किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आम, नीम, कदम, शमी, गूलर, अशोक, कनेर, गुलाब, बादाम , सतपढ़नी, पंचपढ़नी आदि पौधों का रोपण किया गया।

एक दिवसीय कार्यशाला में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को किया जागरुक

किसान करें श्रीअन्न की खेती, फसल को ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

श्रीअन्न की उत्पादन तकनीक विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला में महिला किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ बीएस किरार साथ ही केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. यूएस धाकड़, डॉ. एसके जाटव, डॉ. आईडी सिंह, हंसनाथ खान और राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य महिला मोर्चा भाजपा की आयुषी श्रीमाली, जिला अध्यक्ष भाजपा विभा श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा शर्मा, रिंकी भदौरा, पूनम अग्रवाल, सुशीला राजपूत, आदि उपस्थित रहे। आयुषी श्रीमाली द्वारा महिला किसानों को श्री अन्न के महत्व को बताया कि इसको आहार में सामिल करने पर कई बीमारियों को दूर किया जा सकता है। साथ की बताया की देश के प्रधानमंत्री द्वारा इस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है।

कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार ने महिला किसानों को बताया कि श्रीअन्न को अधिक पानी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यह अधिक तापमान में भी आसानी से पैदा किए जा सकते हैं। यह फसलें किसानों के लिए अच्छी हैं, क्योंकि उनकी खेती करना दूसरी फसलों की तुलना में आसान है। यह कीट पंतगों से होने वाले रोगों से भी बचे रहते हैं। केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. एसके जाटव ने महिला किसानों को कहा कि हम सब जानते हैं कि हरित क्रांति से पूर्व हमारे भारत में उत्पादित होने वाले खाद्यान में मिलेट फसलों की प्रमुख भूमिका थी। आधुनिकता की दौड़ में न केवल जीवन शैली में बदलाव आया, बल्कि हमारा खान-पान भी पूरी तरह बदल गया। आज से पांच दशक पहले हमारे खान-पान की परम्परा बिल्कुल अलग थी। मोटे अनाज हमारे भोजन के मुख्य घटक थे।

मिलेट फसलों की पैदावार में भारत सबसे आगे

60 के दशक में आई हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की खेती को अधिकतम महत्व दिया गया और परिणामत: गेहूं और चावल को हमने अपनी भोजन की थाली में सजा लिया। श्री अन्न को खाद्य श्रृंखला से बाहर कर दिया। हरित क्रांति के पश्चात इनकी जगह धीरे-धीरे गेहूं और धान ने ले ली। भारत आज भी मिलेट फसलों की पैदावार के मामले में विश्व में सबसे आगे है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हरियाणा, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसान बड़े पैमाने पर श्री अन्न यानी मिलेट की खेती करते हैं। मिलेट फसलें ज्यादा पोषक तत्व डॉ. जाटव ने यह भी जानकारी दी कि मिलेट फसलें पोषक तत्वों के लिहाज से पारंपरिक खाद्यान गेहूं और चावल से ज्यादा उन्नत हैं। मिलेट फसलों में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होने की वजह इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। इनमें काफी बड़ी मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, रहता है। कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन कैल्शियम, मैग्नीशियम भी समुचित मात्रा में पाया जाता है। मिलेट फसलों के बीज में फैटो नुत्रिएन्ट पाया जाता है। जिसमें फीटल अम्ल होता है, जो कोलेस्ट्राल को कम रखने में सहायक साबित होता है।

जैविक खेती भी करें किसान

डॉ. जाटव ने बताया इन छोटे दाने वाले, मिलेट अनाजों को आमतौर पर कदन्न अनाज भी कहा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भारत की पहल के अनुरूप पर यूएनओ ने वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। इस को दोनों के आकार के मुताबिक, मिलेट फसलों को मुख्यत: दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। प्रथम वर्गीकरण में मुख्य मोटे अनाज जैसे बाजरा और ज्वार आते हैं तो दूसरे वर्गीकरण में छोटे दाने वाले मिलेट अनाज जैसे रागी, सावा, कोदो, चीना, कुटुकी और कुकुम को सम्मिलित किया है। केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. यूएस धाकड़ द्वारा बताया गया कि प्राकृतिक खेती में जीवामृत, घनजीवामृत, संजीवक, अच्छादन को अपना कर खेती को रसायन मुक्त बना सकते हैं।

किसानों के साथ कृषि के छात्र लेंगे ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव

टीकमगढ़। कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ से बीएससी कृषि फाइनल ईयर के छात्रों को ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव के लिए डॉ. वीणापाणी श्रीवास्तव(प्रमुख वैज्ञानिक), डॉ. एमके नायक (सहायक प्राध्याक) एव डॉ. आरएस सिसोदिया (रिसर्च एसोसिएट) द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव जिला छतरपुर में 20 छात्रों को 6 माह के लिए प्रायोगिक अनुभव (प्रशिक्षण) के लिए लाया गया। छात्र किसानों के बीच रहकर अपने बीएससी (कृषि) डिग्री में सीखे ज्ञान को किसानों को बताएंगे साथ ही किसानो से भी रावे छात्र सीखेंगे। जिसके प्रभारी डॉ. कमलेश अहिरवार (वैज्ञानिक उद्यानिकी) ने रावे छात्राओं को बीएससी डिग्री में प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान को किसानों के बीच कैसे पहुंचना है और किसानों की समस्या को किस प्रकार से हल करना है विस्तार से बतलाया डॉ. एमके नायक ने कृषि के विभिन्न पहलू के महत्व को विस्तार से बतलाया। डॉ. वीणापाणी श्रीवास्तव ने बताया कि कॉलेज लाइफ में कैसे रहना है और कृषि को कैसे लाभ का धंधा बनाना है और डॉ.आरएस सिसोदिया ने भी छात्रों को अनुशासन में 6 माह किसानों के बीच रहकर किस प्रकार कार्य करना है विस्तार से बतलाया। कृषि मौसम वैज्ञानिक हेमंत कुमार सिन्हा ने बताया कि मौसम का कृषि पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है उसको विस्तार से अवगत कराया।

वैज्ञानिकों द्वारा मूंगफली के खेतों का भ्रमण और तकनीकी सलाह

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र, टीकमगढ़ के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, डॉ. बीएस किरार एवं वैज्ञानिक, डॉ. यूएस धाकड़ एवं अनुराग तिवारी, विकासखण्ड तकनीकी प्रबंधक आत्मा द्वारा ग्राम पॉली, घूरा एवं महेन्द्रमहेबा, विकासखंड पलेरा के कृषक दशरथ अहिरवार, दीपचंद पाठक, महेन्द्र विश्वकर्मा आदि के मूंगफली प्रक्षेत्रों पर भ्रमण किया। मूंगफली के विपुल उत्पादन के लिए वैज्ञानिक सलाह प्रदान की। मूंगफली फसल में फूल आने के पूर्व निदाई गुड़ाई के बाद मिटटी चढ़ाने का कार्य करें। मूंगफली में सफेट लट (व्हाइट ग्रब) का प्रकोप शुरू हो गया है सफेट लट, सफेद रंग की मोटी इल्ली होती, जिसका व्यस्क भूरे रंग का होता है जो सांयकाल जमीन से निकल कर पेड़ों की पत्तियो पर बैठा रहता है। बड़े पौधों को नुकसान पहुचाता है। सफेट लट जमीन में रहकर पौधों की जड़ों को खाती रहती है। इसके कारण पौधे सूखे दिखाई देते हैं। अत्याधिक प्रकोप के कारण फसलों को लगभग 20 से 40 प्रतिषत तक नुकसान हो जाता है। इस इल्ली के वयस्कों को पकड़ने के लिये एक प्रकाश प्रपंच प्रति हैक्टेयर की दर से प्रयोग करें। कार्बाफुरोन 3 जी की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयार कर दर से 40 से 50 किलोग्राम रेत मे मिलाकर भुरकाव करें। मूंगफली में पत्तियों पर धब्बा रोग के प्रकोप के नियंत्रण के लिए रेडोमिल 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अधिक वर्षा की स्थिति में जल निकास का कार्य किसान भाई आवश्यक रूप से करें।

कृषि विज्ञान क्रेंद पहुंचे कुलपति

रायसेन। कृषि विज्ञान केंद्र, रायसेन एवं मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी सीहोर के संयुक्त तत्वाधान में बीएससी कृषि अंतिम वर्ष के छात्रों के ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव एवं कृषि औद्योगिक संयोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार पाण्डे, डीन देवेश कुमार पांडे व वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रमुख डॉ. स्वप्निल दुबे, डॉ. अंशुमन गुप्ता, वैज्ञानिक रंजीत सिंह राघव, अरुणा सोमकुंवर प्रमुख रूप से मौजूद थे। डॉ. स्वप्निल दुबे ने कहा कि ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों का किसानों एवं वैज्ञानिक के बीच में रहकर प्रायोगिक कृषि अनुभव प्राप्त करना एवं बीएससी कृषि डिग्री से प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान को कृषकों तक पहुंचा कर उनकी समस्या हल करना है। वैज्ञानिक रंजीत सिंह राघव ने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान छात्र गांव का सर्वे, किसानों की आर्थिक स्थिति, फसलों की उत्पादन लागत एवं विभिन्न विषय फसल उत्पादन, मृदा विज्ञान, उद्यानिकी, कीट विज्ञान और संरक्षण, कृषि अभियांत्रिकी, कृषि प्रसार संबंधी तकनीक सीखेंगे। प्रोफेसर अरुण कुमार पांडे ने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान छात्र कृषि की आधुनिक उन्नत तकनीक उन्नत कृषि यंत्र नवीनतम के संग प्राकृतिक खेती जैविक खेती आदि के जानकारी लेकर कृषि को लाभकारी धंधा बनाने की तकनीक सीखेंगे। कुलपति एवं वैज्ञानिक द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र के विभिन्न प्रदर्शन इकाई नेट हाउस, पॉलीहाउस, ड्रिप एवं मल्चिंग तकनीक, केंचुआ खाद इकाई, प्राकृतिक खेती, फसल संग्रहालय, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला आदि का भी भ्रमण किया गया। इस कार्यक्रम में मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉ. सच्चिदानंद मिश्रा, डॉ. छोटेलाल गौर, डॉ. पवन कुमार पारा, डॉ प्रज्ञा सौरभ उपस्थित थे। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र, रायसेन के वैज्ञानिक डॉ. मुकुल कुमार, डॉ. प्रदीप कुमार द्विवेदी, लक्ष्मी चक्रवर्ती, आलोक कुमार सूर्यवंशी, डॉ. ब्रम्हानंद शुक्ला, पंकज भार्गव, सुनील केथवास का अहम योगदान रहा।

प्रदेश में मिर्च का सर्वाधिक रकबा 46556 हैक्टेयर जिले में रहा

खरगोन की मिर्च को मिलेगी दुनिया में पहचान

संजय शर्मा, खरगोन । जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश शासन अपने दो दशक के विकास कार्यों को विशेष पहचान दिलाने में लगी हुई है। विकास पर्व के तहत खरगोन जिले की लाल सुर्ख मिर्च को विशेष उत्पाद का दर्जा मिलने जा रहा है। प्रदेश के विशिष्ट उद्यानिकी 46 उत्पाद में जिले की तीखी मिर्च को भी शामिल किया गया है। इसके लिए मिशन मोड में काम चल रहा है। इस वित्तीय वर्ष में जियो टैग की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। प्रदेश में 2023 में सर्वाधिक 46556 हेक्टेयर रकबे में जिले में मिर्च फसल बोई गई। उल्लेखनीय है कि देश की दूसरी व मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बेडिया मिर्च मंडी खरगोन जिले में स्थापित है। यहां की मिर्च फसल की ब्रांडिंग होने से गुणवत्ता और कारोबार की उम्मीद बढ़ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में उद्यानिकी उत्पादों की स्थिति का सर्वे कराया। उनमें विशिष्ट पहचान वाले 46 उद्यानिकी उत्पादों को विशिष्ट पहचान देने की दिशा में पहल शुरू की गई है। विभागीय अफसरों का कहना है कि आगामी सीजन में उद्यानिकी उत्पाद जब तैयार हो जाएगा। तब विशिष्ट मापदंडों पर खरा उतरने पर निर्यात करने का अवसर मिलेगा। इसमें अधिक संख्या में किसानों की सहभागिता हो इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं।

इन उद्यानिकी उत्पादों को मिलेगी पहचान

मध्यप्रदेश के विशिष्ट उद्यानिकी उत्पाद के अंतर्गत जबलपुर का मटर, गुना का कुम्भराज धनिया, बुरहानपुर का केला, सिवनी का सीताफल, खरगोन की मिर्च, इंदौर का जीरावन, मालवी आलू आदि 46 विशेष उत्पादों को शामिल किया गया है। शासन स्तर से उत्पादों को भौगोलिक पहचान दिलाने की तैयारी की जा रही है। शासन का मानना है कि यहां के उत्पादों विश्व स्तर पर उत्पाद की ब्रांडिंग होगी 'जीआई टैग' यानी विशिष्ट भौगोलिक पहचान। जीआई टैग मिलने से फ़सल उत्पाद की ब्रांडिंग होगी। इससे उसे वैश्विक पहचान मिलेगी। बाहरी बिचौलियों का हस्तक्षेप खत्म होगा। किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर की बेडिया मिर्च मंडी जिले में है। शासन की इस पहल से यहां के कारोबार में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस पहल से प्रदेश के साथ जिले की समृद्धि बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

5 साल में मिर्च का रकबा व उत्पादन

वर्ष	रकबा	उत्पादन
2018-19	25369	63423
2019-20	23280	81480
2020-21	49052	171682
2021-22	51350	179725
2022-23	46556	139668

(उद्यानिकी विभाग के आंकड़े, मेट्रिक टन में)

इसी वित्तीय वर्ष में हो जाएगा काम

उपसंचालक उद्यानिकी श्री केके गिरवाल ने बताया कि मिर्च का रकबा, कृषि अनुसंधान केंद्र के रिसर्च पेपर, इंडस्ट्रीज सहित सारे इनपुट भेजे गए हैं। सरकार के सलाहकार रजनीकांत डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। 3 माह में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मिशन मोड में काम चल रहा है। संभवत इस वित्तीय वर्ष में मिर्च को जीआई टैग मिल जाएगा।

पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव का भी महत्वपूर्ण योगदान

कृषि मंत्री रहते हुए कसरावद विधायक सचिन यादव ने कसरावद में राष्ट्रीय मिर्ची की

महोत्सव कराया था। एक जिला एक उत्पाद मे इस फ़सल का चयन कराया था। इसके बाद से इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। तबसे लगातार मिर्ची का रकबा बड़ रहा है। किसानों को वाजिब दाम दिलाने का यह प्रयास अब रंग लाया है।

किसानों के खेतों का डिजीटल रिकॉर्ड भी शामिल किया जाएगा

मध्यप्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में होगा डिजिटल फसल सर्वेक्षण

नई दिल्ली/भोपाल । जागत गांव हमार

केंद्र सरकार ने खेतो की फसल के डेटा का एक सत्यापित करने के लिए देश के 12 राज्यों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण नाम से एक पायलट परियोजना शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही यह जलवायु परिवर्तन के प्रति कुछ फसलों की संवेदनशीलता का भी अध्ययन करेंगे। इस डिजिटल फसल सर्वेक्षण एप्लिकेशन को एक ओपन-सोर्स, ओपन-स्टैंडर्ड और इंटर-ऑपरेबल पब्लिक गुड के रूप में विकसित किया गया है, जो हमारी खेत की जमीन की सटीक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसी प्रौद्योगिकियों के साथ भू-संदर्भित मानचित्रों का उपयोग करेगा।

बोई गई फसल का डेटा इकट्ठा किया जाएगा- इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य फसल क्षेत्रों का सही अनुमान और किसानों को हो रही समस्याओं के समाधान के लिए बोई गई फसल का डेटा इकट्ठा करेगा। जो हमारी जमीन का एक विश्वसनीय और सत्यापित स्रोत होगा। इस डाटा के आधार पर देश में गेहूं और चावल की आपूर्ति में कमी की मौजूदा चुनौतियों को सही करने का फैसला लेने में आसानी होगी। जैसे कि देश के किन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन अच्छ है और कैसे इसे और बेहतर बनाया जा सकता है।

जलवायु परिवर्तन का असर

जलवायु परिवर्तन का फसलों की पैदावार पर प्रभाव पड़ रहा है। देश में चावल, गेहूं, मक्का और सरसों का उत्पादन कम होता जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने जलवायु परिवर्तन को लेकर कृषि में नवाचार की बात की है। इस प्रक्रिया में सरकार जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) के ढांचे के आधार पर , योजना बना रहा है। इस परियोजना के तहत बहुत उच्च जोखिम श्रेणी में 109 जिले और उच्च जोखिम श्रेणी में 201 जिलों की पहचान की गई है। इन कमजोर क्षेत्रों में फसल की पैदावार पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए सरकार जलवायु-लचीली कृषि पद्धतियों की आवश्यकता पर जोर देने का विचार कर रही है।

इन राज्यों में होगा सर्वेक्षण

डीसीएस पायलट के लिए चयनित राज्यों में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम शामिल हैं। इन राज्यों को डीसीएस के लिए पूर्व-अपेक्षित मानदंडों के आधार पर चुना गया है। इसमें गांव के मानचित्रों का भू-संदर्भ और स्वामित्व सीमा के साथ खेतों का डिजीटल रिकॉर्ड भी शामिल किया जाएगा।

रोग व कीटों से जुड़ी सभी परेशानी होंगी हल, जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर

नई दिल्ली । जागत गांव हमार

फसलों में लगने वाले खतरनाक रोग की परेशानी को देखते हुए बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन ने किसानों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 8630641798 जारी किया है। यह व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है। जवाब सुबह 9 से शाम को 5 तक भेजा जाएगा। इस एक नंबर से किसानों को कीट से लेकर अन्य कई तरह की परेशानियों का हल सरलता से प्राप्त होगा। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी फसल में लगे रोग व कीटों की एक फोटो को खींचकर इस नंबर पर कॉल करके उन्हें भेजना होगा। आप चाहे तो फसल की विडियो बनाकर भी इस नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि आप समस्या से निजात पा सकें।

नंबर की सेवा टाइमिंग

ऊपर बताया गया नंबर किसानों के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पर किसानों की परेशानी का जवाब सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही मिलेगा। इस दौरान किसान कॉल करके भी फसल से जुड़ी समस्या पर बात कर सकते हैं।

इन कीटनाशकों पर लगा है बैन

अगर किसान इस बात से अभी तक अनभिज्ञ है कि सरकार के द्वारा किन-किन कीटनाशकों पर बैन लगाया गया है। बासमती उत्पादक पंजाब ने 10 कीटनाशकों को बैन किया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। थियामेथोक्सम, प्रोफेनोफोस, इमिडाक्लोप्रिड, कार्बेन्डाजिम, ट्राइसाइक्लाजोल, एसेफेट, बुप्रोफेजिन, क्लोरपाइरीफोस, हेक्साकोनाजोल और प्रोपिकोनाजोल आदि शामिल हैं।

शिवराज बोले-जिन्सों की आवक और मंडी की आय में सर्वाधिक इजाफा

कृषि उपज मंडी व्यवस्था के कारण किसानों को फसलों का उचित मूल्य

» बोर्ड के शेष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भी आमेलन किया जाएगा

» मुख्यमंत्री कृषि विपणन बोर्ड के स्वर्ण-जयंती महोत्सव में शामिल हुए

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कृषि उपज मंडी की उत्तम व्यवस्था के कारण किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल पा रहा है। यह सब आप सबके निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि मंडी समितियों ने जिन्सों की आवक और मण्डी की आय में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि हासिल की है। मैं प्रदेश के सभी किसानों और मण्डी बोर्ड की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री प्रशासन अकादमी में मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के स्वर्ण-जयंती महोत्सव में संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन और कन्या-पूजन के साथ महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर,मप्र के कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रो. सचिन चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमारिया, गौरीशंकर बिसेन, राज्य कृषि विपणन बोर्ड की उपाध्यक्ष मंजू दादू, दर्शन सिंह चौधरी ने भी संबोधित किया।

मूलतः हम सभी किसान मुख्यमंत्री ने कहा कि मूलतः हम सभी किसान हैं। मैंने खेती-किसानी की है और हल-बक्खर चलाया है। अतः किसानों के दुख-दर्द और परेशानियां समझते हैं। सरकार किसानों के कल्याण और उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बोर्ड के शेष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भी आमेलन किया जाएगा। प्रदेश में किसानों को हर तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं।

व्यवस्था को पारदर्शी बनाया

सीएम ने कहा कि किसान अब एमपी फार्म एप के माध्यम से वे अपनी कृषि उपज को अपने घर, खेत अथवा गोदाम कहीं से भी आसानी से विक्रय कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक तौल-कांटे से लेकर बोली लगाने के लिए सरकारी कर्मचारी तक की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है। किसानों को अपने खेत-खलिहानों से ही फसल बेचने की सुविधा दी गई है। बोर्ड के अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि मंडी में जो नीलामी होती है, उसमें दो प्रतिशत से अधिक कमीशन न काटा जाए। भविष्य में भी बोर्ड निरंतर किसानों के कल्याण और प्रदेश के विकास के लिये कार्य करता रहेगा।

मप्र जीत रहा कृषि कर्मण अवार्ड

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश दिन दूनी-रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर निरंतर कृषि कर्मण अवार्ड जीत रहा है। यह हमारे प्रदेश के किसानों के परिश्रम का प्रतिफल है। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि सरकार ने किसानों को कई सौगातें दी हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में किसान को अतिरिक्त आय अर्जित हो रही है। कार्यक्रम में हम्मालों और तुलावटियों को सम्मानित किया गया।

सीएम शिवराज सिंह ने नए अलाइनमेंट सर्वे के दिए आदेश

केंद्र और किसानों की आपत्ति के बीच अटक गया अटल प्रोग्रेस-वे

मुरैना। जागत गांव हमार

चंबल अंचल के लिए मप्र और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अटल प्रोग्रेस-वे परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई है। इस एक्सप्रेस-वे को बीहड़ों में पर्यावरण मंत्रालय नहीं बनने दे रहा और निजी क्षेत्र पर निर्माण के लिए किसान अपनी जमीन देने तैयार नहीं। किसानों के तीव्र विरोध के कारण मार्च महीने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अटल प्रोग्रेस वे के सर्वे को निरस्त कर दिया और दुबारा सर्वे के आदेश दिए। चार महीने से अटल प्रोग्रेस-वे के नए अलाइनमेंट का काम ठप है। 2017 में सरकार ने बीहड़ों में एक्सप्रेस-वे बनाने की घोषणा सरकार ने की थी। उस समय इसका नाम चंबल एक्सप्रेस-वे रखा गया, जिसका नाम पांच बार बदला और अंत में अटल प्रोग्रेस-वे हुआ। 2021 तक इसके अलाइनमेंट का सर्वे हुआ और भारत सरकार ने इसे भारत माला परियोजना में भी शामिल कर लिया, लेकिन एनजीटी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बीहड़ों में एक्सप्रेस-वे बनाने पर यह कहकर रोक लगा दी कि इससे चंबल नदी के जलीयजीवों व बीहड़ के पर्यावरण को खतरा होगा। सरकार ने बीहड़ से दूर इस एक्सप्रेस-वे को बनाने की योजना बनाई। पहले अलाइनमेंट में 162 गांवों से होकर गुजरने वाला यह एक्सप्रेस-वे नए अलाइनमेंट में चंबल संभाग के 214 गांवों से गुजरता, इसके लिए मुरैना के 110, श्योपुर के 63 और भिंड के 41 गांवों यानी कुल 214 गांवों में किसानों की जमीन अधिग्रहण के लिए सर्वे भी हो गया। इसी बीच किसानों का विरोध के होने लगा। असर यह हुआ कि चार महीने पहले सीएम ने सर्वे को निरस्त कर फिर से सर्वे करने के आदेश दिए।

विरोध में उतरे थे किसान

अटल प्रोग्रेस वे के दूसरे सर्वे में सरकारी से कहीं ज्यादा किसानों की जमीन आ रही थी। मुरैना, भिंड और श्योपुर जिले में सरकारी क्षेत्र की 140.36 हेक्टेयर जमीन आ रही थी, जबकि निजी क्षेत्र की 1778.299 हेक्टेयर जमीन आ रही थी। 3000 से ज्यादा किसान प्रभावित हो रहे थे और कई किसान भूमिहीन होने की कगार पर पहुंच गए थे। मुरैना, श्योपुर और भिंड जिले में क्षत्रिय महासभा, किसान महासभा, माकपा आदि संगठनों के साथ किसानों ने जमकर विरोध किया था।

मार्च महीने पहले पुराना सर्वे निरस्त हो चुका है। उसके बाद नए सर्वे के लिए कोई आदेश नहीं आए। मैं एनएचआइ को पत्र लिख चुका हूं, लेकिन उनकी ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई कि नए अलाइनमेंट का सर्वे कब होना है। इस मामले में शासन स्तर से जो निर्देश मिलेंगे, उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा।

अंकित अस्थाना, कलेक्टर, मुरैना

सीएम ने कलेक्टरों को दिया था जिम्मा

28 मार्च मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंबल संभाग के विकास के लिए अटल प्रोग्रेस-वे बनाया जा रहा है, जो श्योपुर, मुरैना, भिंड जिले से निकाला जा रहा है। इस पर 8000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि अटल एक्सप्रेस-वे का जो सर्वे हुआ है, उसमें किसानों की बेशकीमती जमीन जा रही है। हम किसानों को भूमिहीन नहीं होने देंगे, इसलिए अटल प्रोग्रेस-वे के लिए नया सर्वे करवाया जाएगा। सीएम ने संभाग आयुक्त सहित संभाग के तीनों जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि दुबारा जमीन चिन्हांकन करें। मुरैना कलेक्टर इसे लेकर दो बार एनएचआइ को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन एनएचएआइ ने कोई जवाब नहीं दिया।

ज्यादा कीमत में खरीदी फसलें फिर बिना भुगतान किए भागे

किसानों से एक करोड़ की ठगी करने वाले गिरफ्तार

विदिशा। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में किसानों के साथ हुई करोड़ों की ठगी के मामले में कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन्होंने पहले तो किसानों से ज्यादा दामों में फसलें खरीदने का सौदा किया फिर बिना भुगतान किए गायब हो गए। किसानों ने पुलिस में शिकायत की थी। दरअसल मामला दो महीना पहले का है। जिले के त्योंदा थाना क्षेत्र के बागरोद कृषि उपज मंडी और ग्यारसपुर क्षेत्र के किसानों से कुछ बाहरी लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गेहूं की खरीदी बाजार मूल्य और मंडी के दामों से अधिक में की थी। ज्यादा भाव मिलने के कारण किसान आसानी से उनके झांसे में आ गए। तकरीबन 39 किसानों द्वारा उन्हें अपनी गेहूं की फसल बेची थी, लेकिन जब भुगतान की बारी आई तो आरोपी भाग खड़े हुए। करोड़ों रुपये की फसल के एवज में किसानों को उनके दाम नहीं मिले, जब किसानों को ठगी का अहसास हुआ तो उन्होंने थाने में इस बात की शिकायत की। मामला जिला स्तर पर पहुंचा, जिसके बाद टीम बनाकर मामले की जांच शुरू की गई। स्थानीय व्यक्ति और कुछ बाहरी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। एएसपी समीर यादव ने बताया कि पूछताछ के दौरान उनकी निशानदेही पर खरीदा गया गेहूं और राशि उनसे वसूलने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। ज्यादा से ज्यादा राशि वसूलने का प्रयास किया जा रहा है। शुरुआती दौर में एक करोड़ 73 लाख रुपए की ठगी की बात सामने आ रही है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 9425048589

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, संपर्क -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)